

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र०, रावलपुर

प्र०क० निगरानी  
विषय

/2019/रतलाम/भू-रा०

विविध-0502/2019/उच्च न्यायालय/भू-रा०

114

- 1- पारस मल पिता नेमीचंद
- 2- प्रकाश चन्द्र कोठारी पिता परसमल कोठारी निवासी गण बजाज खाना जावरा जिला रतलाम म० प्र० मुख्याआम अवि इन्फास्टक्वर्स प्राइवेट लि० तर्फे डायरेक्टर गिरी गुप्ता निवासी बी-407 यशराज रेसीडेंसी जिला इन्दौर म० प्र०

श्री राजी वरिष्ठ शर्मा 2353 नं०  
12/4/19  
प्रस्तुत। प्रादेशिक तर्क हेतु  
दिनांक 1-5-19 निवेदन।

12-4-19

12/4/19

--- आवेदकगण

विरुद्ध

म०प्र० आसन द्वारा

--- अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 में प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1-यहि कि श्री पारसमल पिता नेमी चंद आदि निवासी बजाज खाना जावरा जिला रतलाम म० प्र० द्वारा मु० आ० अवि इन्फास्टक्वर्स प्राइवेट लि० तर्फे डायरेक्टर गिरीश गुप्ता निवासी बी-407 यशराज रेसीडेंसी जिला इन्दौर म०

12/4/19  
12:40 PM

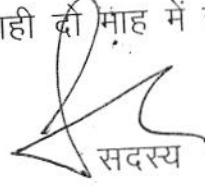
न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

विविध 0502/2019/उज्जैन/भू.रा.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमाकों आदि के हस्ताक्षर
12.4.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया। अनावेदक शासन की ओर से श्री मुकेश शर्मा उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा ग्राह्यता एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 826-एक/2014 में दिनांक 13.2.15 को आदेश पारित कर ग्राम पाण्डयाकला नागदा जिला उज्जैन स्थित भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 14.215 का पुर्ननिर्धारण राशि राजस्व वर्ष 2011-12 से देय होना आदेशित किया गया था। अतः उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी को वर्ष 2011-12 की नवीन दर से पुर्ननिर्धारण करना चाहिये था, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्ननिर्धारण नहीं कर राशि वसूल की जा रही है। इस हेतु आवेदकगण ने पुनः इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण क्रमांक 3061-अध्यक्ष/2016 प्रस्तुत किया गया, जिससे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4.4.18 पारित कर अनुविभागीय अधिकारी को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.2.2015 का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये। इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्ननिर्धारण नहीं किया जाकर राशि वसूली का नोटिस दिया गया है, जो प्रथम दृष्टया ही अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है।</p> <p>2-उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा जारी डायवर्सन टैक्स वसूली का सूचना पत्र क्रमांक 01/भू.प./री./2019 दिनांक 15.3.19 निरस्त किया जाता है।</p>	

✓/2/✓

अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.2.15 एवं 4.4.18 को दिये गये निर्देश के पालन में वर्ष 2011-12 में प्रचलित नवीन दर से पुर्ननिर्धारण कर प्रश्नाधीन भूमि का डायवर्सन किया जावे। उक्त कार्यवाही दो माह में संपन्न की जावे।

  
सदस्य